VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(01 April 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- अमेरिका की 'टैरिफ योजना' और भारत पर इसका संभावित प्रभाव
- 'सहयोग' पोर्टल क्या है, जिसे एक्स (X) ने 'सेंसरशिप पोर्टल' कहा है?
- नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

अमेरिका की 'टैरिफ योजना' और भारत पर इसका संभावित प्रभाव:

चर्चा में क्यों है?

- वैश्विक बाजारों को हिला देने वाले एक नाटकीय कदम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि उनका प्रशासन सभी देशों पर टैरिफ लगाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में आमूलचूल परिवर्तन होगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने 2 अप्रैल को "मुक्ति दिवस" कहा, और पुष्टि की कि ये टैरिफ सार्वभौमिक रूप से लागू होंगे।
- उल्लेखनीय है कि अब तक, अमेरिकी सरकार बड़े व्यापार असंतुलन वाले देशों या अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर लक्षित पारस्परिक टैरिफ पर विचार कर रही थी। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप का नवीनतम रुख इन भेदों को मिटा देता है, और एक व्यापक टैरिफ नीति पेश करता है जो सभी देशों को समान रूप से प्रभावित करेगा।

टैरिफ क्या होता है और देश टैरिफ क्यों लगाते हैं?

- उल्लेखनीय है कि टैरिफ या आयात शुल्क आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। टैरिफ उत्पाद के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होता है।
- आमतौर पर टैरिफ का इस्तेमाल किसी देश के घरेलू उद्योगों को विदेशी देशों से प्रतिद्वंद्वी आयातों से बचाने के लिए एक संरक्षणवादी उपाय के रूप में किया जाता है।
- साथ ही टैरिफ से होने वाली आय सरकारी राजस्व को बढ़ा सकती है, जिसे बदले में सार्वजनिक कल्याण उपायों पर खर्च किया जा सकता है।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के पीछे वजह?

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, टैरिफ "शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द है"। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, टैरिफ अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से असंबंधित मुद्दों पर रियायतें लेने के लिए एक सौदेबाजी की चिप है।
- राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी मानना है कि टैरिफ अन्य देशों के साथ अमेरिका के 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार घाटे को हल करने में मदद कर सकते हैं।
- साथ ही उनका यह भी मानना है कि टैरिफ आयातित उत्पादों की मांग को कम करेगा, और अमेरिकी वस्तुओं की मांग को बढ़ाएगा, बदले में, अमेरिका में विनिर्माण नौकरियों को बढ़ावा देगा।

अमेरिका की पारस्परिक टैरिफ योजना क्या है?

- यह योजना अमेरिका को उन देशों पर टैरिफ/आयात शुल्क बढ़ाने की अनुमति देती है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है।
- राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जबकि अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर अधिक शुल्क और व्यापार बाधाएं लगाते हैं। उनका कहना है कि इससे 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा होता है जो अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों को भी नुकसान पहुंचाता है।

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा कितनी है?

- वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल या वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 फीसदी, आयात में 6.22 फीसदी और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 फीसदी है।
- उल्लेखनीय है कि भारत का अमेरिका के साथ माल या वस्तु व्यापार में, 2023-24 में 35.32 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) है। यह 2022-23 में 27.7 अरब डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब डॉलर था।

भारतीय निर्यात पर 'पारस्परिक टैरिफ' का क्या संभावित प्रभाव होगा?

- GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत को अमेरिकी निर्यात पर वास्तविक आयात शुल्क अक्सर किए जाने वाले दावों से काफी कम है। अगर अमेरिका निष्पक्ष व्यापार दृष्टिकोण अपनाता है, तो भारतीय उद्योग कम से कम व्यवधानों के साथ अमेरिका को निर्यात जारी रख सकते हैं, जिससे अधिक संतुलित और स्थिर व्यापार संबंध को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 'पारस्परिक टैरिफ' के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए GTRI ने चार स्तरों पर पारस्परिक टैरिफ का विश्लेषण किया है।

देश स्तर पर - सभी भारतीय निर्यातों पर एक समान टैरिफ:

- यदि अमेरिका भारत से सभी उत्पादों पर एक ही टैरिफ लगाता है, तो यह अतिरिक्त 4.9 प्रतिशत होगा।
- वर्तमान में, भारत में अमेरिकी वस्तुओं पर 7.7 प्रतिशत का भारित औसत टैरिफ लगता है, जबकि अमेरिका को भारतीय निर्यात पर केवल 2.8 प्रतिशत टैरिफ लगता है, जिससे 4.9 प्रतिशत का अंतर होता है।

कृषि और उद्योग के लिए अलग-अलग टैरिफ:

- यदि अमेरिका अलग-अलग टैरिफ लगाने का फैसला करता है, तो कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त टैरिफ 32.4 प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादों पर 3.3 प्रतिशत होगा।

- अमेरिका को भारतीय कृषि निर्यात पर वर्तमान में 5.3 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि भारत को अमेरिकी कृषि निर्यात पर 37.7 प्रतिशत शुल्क लगता है, जिससे 32.4 प्रतिशत का अंतर पैदा होता है।
- दूसरी ओर, औद्योगिक उत्पादों के लिए, भारत को अमेरिकी निर्यात पर 5.9 प्रतिशत भारित औसत टैरिफ लगता है, जबकि अमेरिका को भारतीय औद्योगिक निर्यात पर केवल 2.6 प्रतिशत शुल्क लगता है, जिसके परिणामस्वरूप 3.3 प्रतिशत का अंतर होता है।

व्यापक क्षेत्र-स्तरीय टैरिफ:

- व्यापक क्षेत्रीय स्तर पर, भारत और अमेरिका के बीच संभावित टैरिफ अंतर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। यह अंतर रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के लिए 8.6 प्रतिशत, प्लास्टिक के लिए 5.6 प्रतिशत, वस्त्र और परिधान के लिए 1.4 प्रतिशत, हीरे, सोने और आभूषणों के लिए 13.3 प्रतिशत, लोहा, इस्पात और आधार धातुओं के लिए 2.5 प्रतिशत, मशीनरी और कंप्यूटर के लिए 5.3 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7.2 प्रतिशत और ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए 23.1 प्रतिशत है।
- उल्लेखनीय है कि टैरिफ अंतर जितना अधिक होगा, क्षेत्र उतना ही अधिक प्रभावित होगा।

सभी उत्पादों को 30 श्रेणियों में समूहित करना:

- भारत का अमेरिका को निर्यात 30 क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें से छह कृषि और 24 उद्योग में हैं, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग टैरिफ प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

कृषि क्षेत्र पर प्रभाव:

- GTRI के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कृषि क्षेत्र मछली, मांस और प्रसंस्कृत समुद्री भोजन होगा, जिसके 2.58 अरब डॉलर के निर्यात पर 27.83 प्रतिशत टैरिफ अंतर का सामना करना पड़ेगा। झींगा, जो एक प्रमुख निर्यात है, काफी कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- 1.03 अरब डॉलर मूल्य के प्रसंस्कृत खाद्य, चीनी और कोको निर्यात भी 24.99 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि के साथ संघर्ष करेंगे, जिससे भारतीय स्नैक्स और कन्फेक्शनरी अमेरिका में महंगी हो जाएगी।
- अनाज, सब्जियां, फल और मसाले, जिनका मूल्य 1.91 अरब डॉलर है, पर 5.72 प्रतिशत टैरिफ अंतर का सामना करना पड़ेगा, जिससे चावल और मसाले के शिपमेंट प्रभावित होंगे।
- 38.23 प्रतिशत टैरिफ अंतर से 181.49 मिलियन डॉलर मूल्य के डेयरी उत्पाद बुरी तरह प्रभावित होंगे।

औद्योगिक उत्पादों पर प्रभाव:

- भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यातकों में से एक, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, जिसकी कीमत 12.72 अरब डॉलर है, को 10.90 प्रतिशत टैरिफ अंतर का सामना करना पड़ सकता है।
- 11.88 अरब डॉलर के निर्यात वाले हीरे, सोने और चांदी पर 13.32 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होगी।
- 14.39 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर 7.24 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जिससे आईफोन और अन्य संचार उपकरण प्रभावित होंगे।
- 7.10 अरब डॉलर मूल्य की मशीनरी, बॉयलर, टरबाइन और कंप्यूटर निर्यात पर 5.29 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि होगी, जिससे भारत के इंजीनियरिंग निर्यात पर असर पड़ेगा।
- 5.71 अरब डॉलर मूल्य के रसायन (फार्मा को छोड़कर) पर 6.05 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है, जिससे भारतीय विशेष रसायनों की अमेरिका में मांग कम हो जाएगी।
- 2.76 अरब डॉलर के निर्यात वाले वस्त्र, फैब्रिक, यार्न और कालीन पर 6.59 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है, जिससे अमेरिका में भारतीय वस्त्र महंगे हो जाएंगे।

'सहयोग' पोर्टल क्या है, जिसे एक्स (X) ने 'सेंसरशिप पोर्टल' कहा है?

चर्चा में क्यों है?

- केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स द्वारा सरकार के सहयोग पोर्टल को "सेंसरशिप पोर्टल" के रूप में वर्णित करना "दुर्भाग्यपूर्ण" और "निंदनीय" है। उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक विस्तृत जवाब में, केंद्र ने भारत के सूचना-अवरोधन ढांचे को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में एक्स (X) कारपोरेशन द्वारा किए गए दावों का विरोध किया।
- उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय वर्तमान में सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर सामग्री को मॉडरेट करने और हटाने का आदेश देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 79(3)(b) के उपयोग करने के खिलाफ एक्स (X) कारपोरेशन की चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।

'सहयोग' पोर्टल क्या है?

- 'सहयोग' पोर्टल को 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने के आदेशों में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया था। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- इस पोर्टल ने भारत में सुरक्षित साइबरस्पेस बनाए रखने की दिशा में त्वरित, समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत एजेंसियों, आईटी मध्यस्थों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को एक ही मंच पर एक साथ लाया।
- राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब के अनुसार सहयोग पोर्टल को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने शबाना बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार के अपने आदेश में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल के संचालन पर जोर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईटी मध्यस्थों को 'सहयोग' पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने और अगली सुनवाई के दौरान उनकी ऑनबोर्डिंग की स्थिति प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सहयोग पोर्टल पर आपत्तिजनक सामग्री को रोकने की प्रक्रिया:

- केंद्र सरकार, राज्य पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी से संबंधित अधिकृत एजेंसी आपत्तिजनक वेब सामग्री को चिह्नित कर सकती है और सहयोग पोर्टल पर इसे ब्लॉक करने का अनुरोध कर सकती है।
- उनका अनुरोध प्राप्त होने के बाद, संबंधित अनुरोध कथित आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने के लिए आईटी मध्यस्थों या ISP के पास जाता है।
- आईटी मध्यस्थों/सोशल मीडिया मध्यस्थों के मामले में, नोटिस सीधे सम्बंधित मध्यस्थ को भेजे जाता है। वहीं ISP के मामले में, नोटिस दूरसंचार विभाग (DoT) को भेजा जाता है और DoT इसे आगे ISP को भेजता है।
- आईटी मध्यस्थों या ISP पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहयोग पोर्टल के राष्ट्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से सभी संबंधित हितधारकों को दिखाई देगी। आईटी मध्यस्थों के पास अधिकृत एजेंसियों से अतिरिक्त जानकारी/साक्ष्य मांगने का विकल्प भी है।

'सहयोग' पोर्टल पर कौन-कौन शामिल है?

- अब तक 15 आईटी मध्यस्थ इस पोर्टल पर आ चुके हैं, जिनमें जोश, क्वोरा, टेलीग्राम, एप्पल, गूगल, अमेजन, यूट्यूब, पीआईडी डेटा सेंटर और शेयरचैट शामिल हैं।

- 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के अनुसार अपने अधिकारियों को अधिसूचित किया है और सहयोग पोर्टल पर शामिल किया है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के बारे में:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है।
- I4C को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
- I4C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार, साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत की समग्र क्षमता में परिवर्तन लाना और नागरिक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है।

नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ:

चर्चा में क्यों है?

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 अप्रैल, 2025 को "नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच (NITI NCAER States Economic Forum)" पोर्टल की शुरुआत की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल राज्यों के वित्त पर लगभग 30 वर्षों (अर्थात 1990-91 से 2022-23) की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, पत्रों और विशेषज्ञ टिप्पणियों पर डेटा का एक व्यापक भंडार है।

पोर्टल के चार मुख्य घटक:

- **राज्य रिपोर्ट:** 28 राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य का सारांश, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर संकेतकों के इर्द-गिर्द संरचित है।

- **डेटा रिपॉजिटरी:** पाँच वर्टिकल: जनसांख्यिकी; आर्थिक संरचना; राजकोषीय; स्वास्थ्य और शिक्षा, में वर्गीकृत संपूर्ण डेटाबेस तक सीधी पहुँच प्रदान करना।
- **राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड:** समय के साथ प्रमुख आर्थिक चरों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करना और डेटा परिशिष्ट के माध्यम से कच्चे डेटा या सारांश तालिकाओं के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी तक त्वरित पहुँच प्रदान करना।
- **शोध और टिप्पणी:** राज्य वित्त और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक शोध पर आधारित है।

'नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच' पोर्टल का महत्व:

- यह पोर्टल समष्टि, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक रुझानों को समझने में मदद करेगा; आसानी से सुलभ डेटा और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप प्रदान करेगा; और एक ही स्थान पर समेकित क्षेत्रीय डेटा की आवश्यकता को भी संबोधित करेगा।
- यह पोर्टल प्रत्येक राज्यों के डेटा को अन्य राज्यों और राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ बेंचमार्क करने में मदद करेगा।

- इसके तहत ऐतिहासिक रुझानों और वास्तविक समय के विश्लेषण का लाभ उठाकर उपयोगकर्ता राज्यों से जुड़े आर्थिक प्रगति को ट्रैक करने, उभरते पैटर्न की पहचान करने और विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां तैयार करने में सक्षम होंगे।
- यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों को सूचित बहस और चर्चा करने के लिए डेटा का उल्लेख करने में रुचि रखने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।
- यह पोर्टल एक व्यापक शोध केंद्र के रूप में काम करेगा, जो गहन शोध अध्ययनों के लिए डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों का खजाना पेश करेगा।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER):

- नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है।
- 1956 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में स्थापित NCAER की शुरुआत तत्कालीन वाणिज्य मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी और उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने औद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए की थी।

MCQs

1. चर्चा में रहे 'भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अमेरिका, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है।
2. 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ माल या वस्तु व्यापार में, 35.32 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(b)

2. हाल ही में नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलकर एक पोर्टल "नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच" लांच किया है। इस पोर्टल के चार घटकों में से निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?

(a) राज्य रिपोर्ट

(b) डेटा रिपॉजिटरी

(c) राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड

(d) उपर्युक्त सभी शामिल हैं।

Ans:(d)

3. चर्चा में रहे अमेरिका की 'पारस्परिक टैरिफ' योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह योजना अमेरिका को उन देशों पर टैरिफ शुल्क बढ़ाने की अनुमति देती है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है।
2. यह अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से असंबंधित मुद्दों पर रियायतें लेने के लिए एक सौदेबाजी की चिप है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. चर्चा में रहे 'सहयोग' पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) इसे इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने के आदेशों में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया था।

(b) इसे सर्ट-इन द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

(c) इसको IT अधिनियम की धारा 66A के तहत नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans:(a)

5. चर्चा में रहे 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है।

2. यह साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार पर बल देता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)